provides Central Assistance for State plans according to a formula in which higher weightage is given to State) which have lower per capita income.

Statement

States with low per capita income

Sl. No.	State/U.T.	Years in which per capita NSDP of State is less than per capita NNP of India.
1.	Andhra Pradesh	1980-81 to 1990-91
2.	Arunachal Pradesh	1980-81
3.	Assam	1980-81 to 1991-92
4.	Bihar	1980-81 to 1991-92
5.	Gujarat	1987-88
6.	Himachal Pradesh	1983-84 to 1988-89 and 1990-91
7.	Jammu & Kashmir*	1987-88 to 1989-90
8.	Karnataka	1980-81 to 1990-91
9.	Kerala	1980-81 to 1991-92
10.	Madhya Pradesh	1980-81 to 1991-92
11.	Manipur	1980-81 to 1991-92
12.	Meghalaya	1980-81 to 1991-92
13.	Mizoram†	1980-81 to 1985-86
14.	Nagaland**	1980-81 to 1982-83, 1985-86, 1986-87, 1988-89
15.	Orissa	1980-81 to 1991-92
16.	Rajasthan	1980-81 to 1991-92
17.	Sikkim	1980-81 to 1983-84 & 1991-92
18.	Tamil Nadu	1980-81 to 1986-87, 1988-89 to 1991-92
19.	Tripura*	1980-81 to 1989-90
20.	Uttar Pradesh	1980-81 to 1991-92
21.	West Bengal**	1980-81 to 1990-91

* Figures for 1990-91 and onwards are not available.

†Figures for 1989-90 and onwards are not available.

**Figures for 1991-92 are not available.

Expansion of NIC's Area of Operation

1856. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Informates Centre is planning to expand its area of operation at block levels in the country;

(b) if so, what are the details of action initiated in this regard;

(c) whether the NIC has already opened its Offices at block levels in some States; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) National Informatics Centre (NIC) has completed the first phase of the pilot project for block level information system in the district of Aligarh in collaboration with Aligarh Muslim University. Action has been initiated for the second phase of the pilot project.

(c) and (d) No, Sir. However, the engineering work for the expansion of NICNET, the computer communication network of NIC from the NIC offices it the district headquarters and to the offices of the Block Development Officers is under progress in the pilot districts of Haryana and Karnataka.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर

1857. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में विकास दर का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास दर प्राप्त करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए नये लक्ष्य निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए औसतन 5.6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) संवृद्धि दर का लक्ष्य है । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992–93 अर्थात् योजना के प्रथम वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 4.2 प्रतिशत होने की संभावना है । वर्ष 1993–94 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) पंचवर्षीय योजना संवृद्धि लक्ष्य, पांच वर्ष की अवधि के लिए औसत आधार पर तय किए जाते हैं, न कि वर्ष आधार पर । आशा की जाती है कि आठवीं योजना के सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ।

आंतरिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में विश्व-बैंक का अध्ययन

1858. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक अपने हाल के अध्ययन के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि देश में गरीबी बढ़ने का एक मात्र कारण उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग होना है तथा क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए देश के संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करने हेतु वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए तैयार किए गए कंट्री इकॉनोमिक मैमोरेंडम (पैरा 3.43), में यह बताया गया है कि "भारत में लगभग 866 मिलियन जनसंख्या है (मध्य 1991), जिसका एक चौथाई से अधिक हिस्सा सरकारी गरीबी की रेखा से नीचे रहता है तथा जो अब भी लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।" यहां वृद्धि का संदर्भ जनसंख्या में वृद्धि से है ।